259

## LOK SABHA

Monday, 28th February, 1955

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

\*२८२. श्री अवत वृशीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करोंगे कि :

- (क) क्या सरकार को यह शिकायत मिली हैं कि अनेक ग्रामीण हाक घरों में मनीआर्डर बहुत लम्बा समय बीत जाने पर बितरित किथे जाते हैं; और
- (ख) यदि हां, तो इस परिस्थिति में सुधार करने के लिये कॉन कॉन से विशेष उपाय किये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां. कहीं कहीं।

- (स) (९) जहां-कहीं आवश्यक हो गांव में डाकिए को कहीं बार भेजा जाय।
- (२) छोट' डाक-घरां की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाय।
- (२) जहां कहीं बांच पोस्टमास्टरों के कार्य में शिथिलता पाई जाय वहां अधिक निगरानी की जाय ।

श्री अक्त वृज्ञीन: क्या माननीय मंत्री महौदय ने इस सुभाव पर भी विचार किया हैं कि मनीआर्डरों के वितरण में दंरी होने का एक मुख्य कारण यह हैं कि एक्सट्रा डिपार्टमेंटल 670 LSD. एबेंटों व पोस्टमेंनों को बहुत कम परिमाण में रुपये ले जाने का अधिकार हैं, इसिलचें उनसे और अधिक जमानत लेकर भी जन्में विभागीय पोस्टमास्टरों व पोस्टमेंनों के बसबर रुपये ले जाने का अधिकार दिया जाय ?

26 D

श्री राज बहादुर: एक विलोज पोस्टमेंन कुल २४० रुपये की रकम के मनीआर्डर से जा सकता हैं, उसमें भी कोई मनीआर्डर ४० रुपये से ज्यादा का वह नहीं ले जा सकता हैं। उनको ज्यादा रुपये जाने में जो एक सबसे बड़ी समस्या हैं, वह हैं उनको सुरक्षा की, इसलिये इस पर विचार अभी दुशवार हैं।

श्री भक्त दर्शन: क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्याम में यह बात भी आई है कि कई एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब व बांच पौस्ट आफिसों के पौस्टमास्टर मनीआईरों के रुपये अपने व्यापार में लगा दंते हैं और फलस्वरूप गामीणों को बहुत दंर से वे मनीआईर वितरित किये जाते हैं, क्या इस प्रकार के दोषी पौस्टमास्टरों के विरुद्ध कोई विशेष कार्यवाही की गई हैं या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा हैं?

श्री राज बहाचुर: एंसी शिकायत विशेष रूप से कोई नहीं मिली, यदि माननीय सदस्य के नोटिस में कोई एंसी शिकायत आई हो और मुभ्र तक भिजवाने की कृपा करेंगे. तो में बढ़ा आभारी होंगा।

Shri T. B. Vittal Rao: May I know if it is a fact that there are three lakhs of villages in India where the mails are delivered only once in a week and so, in such places, what is the average time taken to deliver money orders?

Shri Raj Bahadur: About a couple of years ago, there were thousands of ' villages-I thousands and lakh or about think -where the postmen never went or never visited them. They were known as 'no dak' villages. We have now eliminated these 'no dak' villages and there is now not a single village anywhere in the country which postman does not visit at least once a week.

## CENTRAL TRACTOR ORGANISATION

- \*284. Shri Dabhi: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1002 on the 10th December. 1954 and state:
- (a) whether Government have since taken any decision on the various recommendations on the working of the Central Tractor Organisation made by the Estimates Committee in their Seventh Report; and
- (b) if so, the nature of the decisions taken?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): (a) and (b). Government have not yet completed examination of the Report. The matter is expected to be finalised very shortly.

Shri Dabhi: May I know the approximate time that the Government will take for examining the matter and arriving at a conclusion?

Dr. P. S. Deshmukh: I expect it would not take more than about two weeks.

सेठ गोविन्द दास: इसमें कितने ट्रॅक्टर एंसे हैं कि जो अतिरिक्त हिस्सों के न मिलने कारण बेकाम पह हुए हैं और इन अतिरिक्त हिस्सों को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० दंशमुख: शायद मेम्बर साहब को माल्म होगा कि में ने इसका जवाब चन्द रोज हुए दिया था, पिछले सेशन में दिया था कि फिलहाल सेंट्रल ट्रॅक्टर आरगनाइजेशन में कोई एंसा ट्रॅक्टर नहीं हैं जो हम इस्तैमाल नहीं करते हैं, जो हमें सरप्लस हैं या काम में नहीं आ सकता है वह हमने डिस्पोजल की तरफ भेज दिये हैं।

श्री गिडवानी: क्या माननीय मंत्री को माल्म हैं कि सेंट्रल ट्रॅक्टर आरगनाइ जेशन के गौदाम में कर्ड ट्रॅक्टर पड़ें हैं जो ध्प में और वर्षा में पड़ें हैं, किसी काम में आने वाले नहीं हैं और जंग भी लगा हुआ हैं?

डा० पी० एस० इंशामुखः यह शायद हालत चन्द दिनों के पहले थी। जहां तक मुक्तें इल्म हैं, अब एंसा नहीं हैं।

Shri Kelappan: May I know if any amounts from the State Governments have been collected since 31st March, 1954?

Dr. P. S. Deshmukh; I would like to have notice.

AGREEMENT WITH AUTOMATIC TELE-PHONE AND ELECTRIC COMPANY LTD.

\*285. Shri Jhulan Sinha: Will the Minister of Communications be pleased to state whether any action has been taken on the suggestions made by the Public Accounts Committee to get the agreement with the Automatic Telephone and Electric Company Ltd. revised in respect of the points enumerated by the Committee in their Tenth Report?

The Deputy Minister of Communications (Shri Raj Bahadur): A statement is laid the Table of the Lok Sabha. [See Appendix II, annexure No. 34].

Shri Jhulan Sinha: In view of the remarkes against item 3 of the statement, namely, "This will be kept in view while entering into such agreements in future", may I know if it is not possible to have this clause revised in the agreement itself?

Shri Raj Bahadur: The agreement was concluded as early as 1949, and any modification therein can be effected only by mutual agreement of both the parties. It is not quite certain